संख्या-40/2017/470/22-4-17-48(32)/07

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 14 जून, 2017

विषय- निर्माणाधीन जिला कारागार, इलाहाबाद के निर्माण कार्यों की निरन्तरता बनाये रखने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-18607/नम-2/140/2017, दिनांक 02.06.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-116/2015/363/22-4-15-48(32)/07, दिनांक 15.05.2015 द्वारा जिला कारागार इलाहाबाद के निर्माण की मूल स्वीकृत लागत रू0 16011.29 लाख की लागत पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 1000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। तदोपरान्त शासनादेश दिनांक 15.03.2016 द्वारा रू0 3000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान गयी। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य हेतु अब तक रू0 4000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राजयपाल महोदय जिला कारागार, इलाहाबाद के निर्माण कार्यों की निरन्तरता बनाये रखने हेतु धनराशि रू0 24,04,52,000/- (रूपया चौबीस करोड़ चार लाख बावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान सहर्ष करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं कार्य दिनांक 30.09.2017 तक कर लिया जाय।

(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08- कारागारों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त् लेखाशीर्षक मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

5- शासनादेश दिनांक 15 मई, 2015 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक- 02.01.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-40/2017/470(1)/22-4-17-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री/प्रमुख सचिव, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in